HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gauri Devi Prayavaran Bhawan"
46B, I.T. Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun

UKPCB/HO/ Gen-76/Vol-II/ 2213-437, **Date: 31.07.2021**

To,

The Chairman,
Central Pollution Control Board,
(Ministry of Environment And Forests),
Government of India, 'Parivesh Bhawan',
East Arjun Nagar, Delhi –32.

Sub:- Submission of Annual Report 2020-2021 on Plastic Waste Management Rules, 2016 reg.

Sir,

With reference to the above mentioned subject, the Annual Report for the year 2020-2021 on Plastic Waste Management Rules, 2016 is enclosed for your kind perusal please.

Enclosures: As above

Yours faithfully

(S.P. Subudhi)I.F.S.
Member Secretary

Form- VI

STATE-WISE STATUS OF IMPLEMENTATION OF PLASTIC WASTE MANAGEMENT RULES, 2016, AS AMENDED 2018, FOR THE YEAR, 2020-21

ANNUAL REPORT FORMAT

Name of the SPCB/ PCC	Estimated Plastic Waste generation. Tons per annum (TPA)	No. of registered Manufacturing/ Recycling(including multilayer, compostable) Units (Rule 9)			No. of unregistered Manufacturing or Recycling Units (in residential or unapproved areas.)	Details of Plastic Management (PWM) e.g. Collection, Segregation, Disposal (Co-processing, Road construction. Etc.) (Rules 6) (Attach separate)	Partial/complete ban on usage of Plastic carry bags (through Executive Order) (Attach copy of notification or Executive Order)	Status of Marketing, Labeling on carry bags (Rule 8) {Specify No. of units not compiled} Complied	Explicit Pricing of carry bags (Rule 10)	Details of the meeting of State Level Advisory Body (SLA) along with its recommendations on Implementation (Rule11)	No. of violations & action taken on non-compliance of provision of these rules.	Number of Municipal Authority or Gram panchayat under jurisdiction and submission of Annual Report to CPCB (Rule 12)
		Plastic Units	Compostable Plastic Units	Multilayer Plastic Units								
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
UKPCB, Dehradun	18647.75 Ton per annum. Reported by ULBs	53*	01	28	-15 - (06 are in approved in industrial area) Notice send via letter dated 07.02.2020 **Annexure-1**	Attach **Annexure-2**	Yes, Single used plastic for plastic carry bag and food cutleries and their use, handling, storage, transportation and manufacturing is banned by Uttrakhand Govt. notification no. 84/XXXVIII-120-13(II)/2021, dated 16.02.2021. **Annexure-3**	-	-	State level monitoring committee (SLMC) for plastic waste management has been constituted by State Government on 03.05.2019.	**1.** UKPCB has issued Direction to all District Magistrate for compliance of PWM Rulels, 2016 and ban on plastic on dated 25.06.2019 and 20.07.2021. **2.** Director, Urban Development Directorate, All District Magistrate vide letter dated 28.12.2019. Copy enclosed. **Annexure-4**	Out of 91 ULBs report of 67 ULBs received and no Gram Panchayat report is received in Uttrakhand Pollution Control Board.

*** Out of 53 units 46 is recyclers and 07 are manufacturing units.**

Annexure - 1

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248001

पत्रांक–यूकेपीसीबी / एच.ओ. / ... 1794 दिनांक: .02.2020

सेवा में,

1. **M/s ILMA Traders-dadupur Govindpur, Bahadrabad, Hadridwar.**
2. **M/s MK Traders & Industry (Formerly MK Industries), Bahadrabad.**
3. **M/s Ramsans Polymers Pvt. Ltd., Raipur Industrial Area, Bhagwanpur Roorkee, Haridwar.**
4. **M/s Shine Star Plastic, Vill- Raipur Industrial Area, P.O. Bhagwanpur, Roorkee, Haridwar.**
5. **M/s N.D. Enterprises, Shiv Ganga Industrial Estate, Lakeshwari.**
6. **M/s Raghav Metal Recycling Plant, Vill-Sherpur, Roorkee, Haridwar.**
7. **M/s Sai Industries, Sisona Road, Raipur, Bhagwanpur, Roorkee, Hardiwar.**
8. **M/s Sai Sanyam Industries, Sector-8B IIE SIDCUL, Haridwar.**
9. **M/s Satya Waste Management Industries, Bahadarpur, Saini Post- Daulatpur, Roorkee, Hardiwar.**
10. **M/s Shree Ram Industries, Dev Bhoomi Industrial Estate, Banatakheri.**
11. **M/s Shri Balaji Sales Corporation, Sikanderpur, Bhainswal.**
12. **M/s Vaishali Enterprises, Vill- Kuahedi, P.O. Gurukul Narsan, Teh-Roorkee, Hardiwar.**
13. **M/s Varai Power Pvt. Ltd., Khasra no. 548/30, Vill- Pili, Town-Bahadrabad.**

विषयः– प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत पंजीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** के अन्तर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण में संलग्न उद्योगों/इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश (ओ0ऐ0 247) में बिना पंजीकरण कराये प्लास्टिक रिसाईक्लरस पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। आप की इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण कराये बिना इकाई का संचालन किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि **दिनांक 29.02.2020** तक अपने पंजीकरण हेतु आवेदन शुल्क सहित उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रूड़की में जमा करें अन्यथा बोर्ड द्वारा इकाई के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने को बाध्य होगा जिसके लिये सम्पूर्ण उत्तरदायी स्वयं इकाई होगी।

भवदीय

(पी0के0 जोशी)
पर्यावरण अभियन्ता

प्रतिलिपिः–
1. सदस्य सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित्।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई परिकल्प भवन, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित् कि जिन इकाईयों द्वारा आवेदन जमा नहीं किये जायेंगे उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करना चाहें।

पर्यावरण अभियन्ता

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248001

पत्रांक–यूकेपीसीबी/एच.ओ./ दिनांक .02.2020

सेवा में,

1. M/s Trikuta Enterprises, IDEB Industries, Estate Mahukheraganj.
2. M/s Rathore Langhu Udhyog, Khata no. 08, Khasra no. 944/2, Vill- Nankmata.
3. M/s MH Plastic Industries, Khasra no. 401, Vill- Basi Islamnagar, Hariyawal.

विषयः– प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत पंजीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण में संलग्न उद्योगों/इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश (ओ0ऐ0 247) में बिना पंजीकरण कराये प्लास्टिक रिसाईक्लरस पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। आप की इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण कराये बिना इकाई का संचालन किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29.02.2020 तक अपने पंजीकरण हेतु आवेदन शुल्क सहित उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, काशीपुर में जमा करें अन्यथा बोर्ड द्वारा इकाई के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने को बाध्य होगा जिसके लिये सम्पूर्ण उत्तरदायी स्वयं इकाई होगी।

भवदीय

(पी0के0 जोशी)
पर्यावरण अभियन्ता

प्रतिलिपिः–
1. सदस्य सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित्।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चामुण्डा काम्पलैक्स, रामनगर रोड़, काशीपुर को इस आशय के साथ प्रैषित् कि जिन इकाईयों द्वारा आवेदन जमा नहीं किये जायेंगे उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करना चाहें।

पर्यावरण अभियन्ता

Status of Plastic Waste Management

Segregation of waste:- As per the report of Directorate, Urban Development Directorate.

1. 42 ULBs are segregating, channelizing and sending the plastic to recycle using installed plastic compactor.
2. 06 more compactors are in the process of installation.
3. After installation of 48 plastic compactors, using cluster approach, all 91 ULBs i.e. 100 % will get facility of plastic recycling.
4. Government of India has allocated fund of Rs. 5.2254 crore to Panchyati Raj Department for procurement of 95 plastic compactors to be installed at Gram Panchayat. In 64 Gram Panchayat sites are identified for establishment of plastic compactors.

Details of Plastic Waste Management (PWM)

1. Different major PIBO's like (IPCA, Shakti Plastic Industries, Shukla e-waste processor, GEM, NEPRA, Green Plastic Waste Management Pvt. Ltd., Rekart Innovations Pvt. Ltd.) is collecting plastic waste in Uttrakhand State, in which approx 23091.43712 Ton had been collected by PIBO's April, 2019 to March, 2021. Details as follows:-
   a) Total Plastic Waste, which is co-processed 6653.54 Ton in the year April, 2019 to March, 2021.
   b) Total Plastic waste is recycled 16437.91 Ton by PIBO's in year 2019 to 2021.
2. 10 MTPD plastic processing plant/ "Plastic Fuel" are being proposed in Haridwar on PPP mode.
3. 05 megawatt "Waste to Energy" plant is proposed at Roorkee to utilize the RDF of nearby Town (Roorkee, Haridwar and Rishikesh).
4. Use of waste plastic in road construction has already initiated on trial basis in 03 ULBs (Haldwani, Almora and Dehradun).
5. 01 Material Recovery Faciltiy having capacity of 05 Ton per day is functional at Dehradun and further 03 more Material Recovery Facilities are in the process of establishment.

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
संख्या– 84 / XXXVIII–1–20–13(11) / 2001
देहरादूनः दिनांकः 16 फरवरी, 2021

अधिसूचना

चूंकि, प्लास्टिक अजैवनाशकारी है एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिये खतरा पैदा करता है। प्लास्टिक मिट्टी की उर्वरता को कम कर पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करता है, नालियों और सीवर को बाधित करता है, जिसके परिणामस्वरूप सीवर व नालियों का पानी बाहर बहने लगता है, जिसका मवेशियों व जंगली जन्तुओं द्वारा इसका भक्षण करने पर उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है या वे असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाते हैं;

और चूंकि, प्लास्टिक में मौजूद रंग पिगमेंट, प्लास्टिक में लिपटे खाद्य पदार्थों को दूषित करता है, जो कि स्वास्थ्य के लिये हानिकारक व कैंसर तक का कारण होता है;

और चूंकि, प्लास्टिक से बने उत्पादों को क्षरण होने में कम से कम 100 वर्ष का समय लगता है, क्योंकि प्लास्टिक अजैवनाशकारी होता है। इसके साथ–साथ प्लास्टिक वर्षा के पानी को फिल्टरेशन करने से रोकता है तथा मिट्टी की सतह तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे भू–गर्भीय जल का पुनर्भरण नहीं हो पाता है;

और चूंकि, प्लास्टिक बैग के खुले में निस्तारित किये जाने के कारण वर्षा के दौरान पानी इन प्लास्टिक बैग में जमा हो जाता है, जो कि मलेरिया, डेंगू आदि वेक्टर जनित रोगों के पनपने के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराता है। प्लास्टिक के खुले में जलाये जाने के कारण कैंसरकारी व बेहद जहरीले पदार्थ जैसे कि डॉई–आक्सिक फ्यूरॉन व हाईड्रोजन सॉयनाईड उत्सर्जित होता है, जो वायुमण्डल प्रदूषित करने के साथ–साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का भी कारण है;

और चूंकि, प्लास्टिक अपशिष्ट व माइक्रो प्लास्टिक के कारण ताज़ा जल व समुद्री जल तथा जैव विविधता के लिए खतरे का कारण है और पर्यटक स्थलों, पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील व हमारे धरोहर, जैसे बुग्याल, ऊँचाई वाले क्षेत्र, कृषि व वन को, इसके फैलने से यह पारिस्थितिकी सेवाओं को भी बाधित करता है;

अतः अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड राज्य में प्लास्टिक पर निम्नानसुार प्रतिबन्ध एवं प्रतिषेध अधिरोपित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. **(क)** कोई भी व्यक्ति, स्वयं या किसी और के माध्यम से जानबूझकर या अनजाने में निम्नलिखित प्लास्टिक / थर्मोकोल / स्टायरोफोम सामान के क्रय, विक्रय, उत्पादन, आयात, भण्डारण, ले जाना, उपयोग व आपूर्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में नहीं करेगाः–
   (एक) किसी भी आकार, मोटाई, माप व रंग के प्लास्टिक कैरी बैग (हैंडल के साथ अथवा बिना हैंडल के) और नॉन–वोवन पॉली प्रोपाईलिन बैग :

परन्तु बायो–कम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग एवं 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग, जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन में उपयोग किये जाते हैं, पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(दो) थर्मोकोल (पॉलीस्टायरीन), पॉलीयुरेथेन, स्टायरोफोम और इसी तरह के बने एकल उपयोग के डिस्पोजेबल कटलरी या प्लास्टिक जैसे प्लेट, ट्रे, कटोरे, कप, गिलास, चम्मच, काँटा, स्ट्रॉ, चाकू, स्टिरर आदि चाहे वे किसी भी आकार व प्रकार के हों।

(तीन) एकल उपयोग खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग कन्टेनर चाहे किसी भी आकार, माप, प्रकार व रंग के हों, जो पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने हों व जो खाद्य/तरल पदार्थ को ढ़कने, ले जाने व भण्डारित करने में उपयोग होता हो।

नोटः कम्पोस्टेबल प्लास्टिक भारतीय मानक IS 17088:2008 की पुष्टि करेगा। बायो कम्पोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माता या विक्रेता विपणन या विक्रय से पहले केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस हेतु सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति जानते हुये या अन्यथा की दशा में सार्वजनिक स्थल में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक को, जो कि इस अधिसूचना में अनुमन्य प्लास्टिक है, को नहीं फेंकेगा।

2. धार्मिक स्थलों व संस्थानों, सिनेमाघरों, मॉल, होटल और रेस्तरां, कैफे, मोबाईल फूड काउन्टर या वैन, कैटरर्स और अन्य स्थानों जैसे शादी या पार्टी हॉल, दफ्तर व संस्थान या आउटडोर ईवेन्ट के स्वामी और प्राधिकरण उक्त उपबंधो का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु उत्तरदायी होंगे। इसके साथ–ही–साथ उनके द्वारा जनित प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण हेतु उनके परिसर में स्थान उपलब्ध कराया जायेगा व प्लास्टिक के एकत्रण के पश्चात् उसको उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकृत रिसाईक्लरस को पुर्नचक्रण हेतु भेजा जायेगा।

3. बोतलबन्द पानी व शीतल पेय हेतु पॉलीइथायलीन टेरेफ्थलेट (पीईटी/पीईटीई) बोतलों के उत्पादकर्ता विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के तहत् परस्पर सहमत नियमों और शर्तों के अन्तर्गत एक ही खुदरा बिक्री नेटवर्क के माध्यम से क्रमशः पॉलेथिन टेरेफ्थलेट की बोतलों और प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस लेंगे अथवा उनके उत्पाद द्वारा जनित प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, परिवहन व सुरक्षित निस्तारण हेतु स्थानीय प्राधिकरण (नगर निकाय/ग्राम पंचायत) द्वारा किये गये खर्चों का भुगतान उनके द्वारा आवश्यक रूप से किया जायेगा।

4. ऐसी सभी उत्पादन इकाईयाँ जो बिन्दु संख्या–1(क)(एक) से बिन्दु संख्या–1(क)(तीन) मे निर्दिष्ट उत्पाद बना रहीं हैं, उनको इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि के छः माह के भीतर उपरोक्त उत्पादों का उत्पादन बन्द करना होगा।

5. उपरोक्त उपबंधो के उल्लंघन की दशा में निम्नानुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगाः–

उल्लंघनकर्ता	जुर्माने की धनराशि
उत्पादकर्ता	रू0 5.00 लाख
परिवहनकर्ता	रू0 2.00 लाख
खुदरा विक्रेता/विक्रेता	रू0 1.00 लाख
व्यक्तिगत उपयोग	रू0 100/–
पुनः उल्लंघन में पाये जाने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता पर उपरोक्त का दोगुना अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।	

6. निम्नलिखित अधिकारी निर्देशों के कार्यान्वन और जुर्माना आरोपित करने हेतु अधिकृत होगें:–

1. जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से नीचे का ना हो।
2. नगर आयुक्त/स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो कि सैनेट्री सुपरवाईजर के पद से नीचे का ना हो।
3. पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो दरोगा के पद से नीचे का ना हो।
4. प्रभागीय वनाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो रेंज अधिकारी से नीचे का पद ना हो।
5. आयुक्त, टैक्स विभाग या उनके द्वारा नामित अधिकारी, संयुक्त आयुक्त से नीचे का पद ना हो।
6. आयुक्त, परिवहन विभाग या उनके द्वारा नामित अधिकारी, संयुक्त आयुक्त से नीचे का पद ना धारण करता हो।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उनके द्वारा नामित अधिकारी, सहायक अभियन्ता से नीचे का पद ना हो।

7. उपरोक्त अधिकृत अधिकारियों द्वारा एकत्र किये जाने वाले जुर्माने को सीधे उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग में **"अन्य प्राप्ति मद"**में जमा करायी जायेगी।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/ XXXVIII–1–21–13(11)/2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली.
2. सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष/सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
12. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. आयुक्त, कर विभाग/परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
14. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
15. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

16/2/21

(नेहा वर्मा)
अपर सचिव।

Government of Uttarakhand
Environment, Conservation & Climate Change Section
No. 84 /XXXVIII-1-20-13(11)/2001
Dehradun Dated: 16 February, 2021

Notification

Whereas, plastics are non-biodegradable and cause threat to the ecological system as they reduce the fertility of soil and thereby hamper the growth of plants, choke drains and sewer resulting in overflowing of gutters and if swallowed by cattle and wild animals, they may cause death by obstructing their intestine;

And whereas, the colour pigments present in the plastic contaminate food products wrapped in them and cause health hazards and some of it even carcinogenic;

And whereas, plastic products take hundreds of years for degradation, as they are not biodegradable, they also block the rainwater infiltration into the soil hindering recharge of ground water;

And whereas, the plastic bags when discarded can get filled with rainwater offering ideal breeding ground for vector borne diseases like malaria, dengue etc. and burning of plastics also releases carcinogenic and toxic substances like dioxins, furans and hydrogen cyanide, which pollute air as well as cause severe and chronic health problems;

And whereas, plastic waste and micro plastic cause danger to fresh and marine water bio-diversity and also hamper ecosystem services due to spreading of such waste in and around eco-systems, on tourists places, heritage sites, eco-fragile areas like- Bugyals, high altitude areas and on agriculture and forest areas.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section (1) of section 3 of the Uttarakhand Plastic and Other Non Biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) Act, 2013, the Governor is pleased to allow to impose the restriction and prohibition on plastic as follows: -

1. (a) No person, by himself or through another, shall knowingly or otherwise, **sale, trade, manufacture, import, store, carry, transport, use, supply or distribute** the following plastic/thermocol/Styrofoam items in the entire state of Uttarakhand.

(i) Polythene carry bags of any shape (with or without handle), thickness, size& colour; and non-woven poly propylene bags

Provided above restriction shall not be applicable on bio-compostable plastic bags and polybags more than 50 micron thickness used for handling, collection, transportation of the waste such as bio medical waste, municipal solid waste and hazardous waste.

(ii) Single use disposable cutleries made up of thermocol (polystyrene), polyurethane, Styrofoam and the like; or plastic such as plate,tray, bowl, cup, glass, spoon, fork, straw, knives, stirrer etc. of any size and shape.

(iii) Single use food packaging containers made up of recycled plastics of any size, shape, thickness and colour used to cover, carry, store food/liquid items.

Note: Compostable plastics shall confirm to the Indian Standard: IS 17088:2008. The manufacturers or seller of bio-compostable plastic carry bags shall obtain a certificate from the Central Pollution Control Board before marketing or selling.

(b) No person shall knowingly or otherwise, litter any public place with any plastic item allowed under this notification.

2. The authorities or owners of places of religious worship or institutions, multiplex, malls, hotels and restaurants, cafe, mobile food counters or vans, caterers and other such places like marriage or party halls, offices or institutions and the outdoor event shall be responsible for ensuring strict compliance of the aforesaid provisions and they shall provide space for collection of plastic waste within their campus and shall send it to the recyclers, duly registered with Uttarakhand Pollution Control Board.

3. Manufacturers of Products of Polyethylene Terephthalate (PET/PETE) bottles for bottled drinking water and soft drinks shall take back the Polyethylene Terephthalate (PET/PETE) bottles and plastic waste respectively through the same retail sales network under mutually agreed terms and conditions based on Extended Producer's Responsibility or they have to mandatorily compensate expenses incurred by the local authorities (Urban Local Bodies and Village Panchayats etc.) in collection, transportation and safe disposal of the plastic waste generated due to their products.

4. All manufacturing units engaged in manufacturing of the items as mentioned under clause 1(a)(i) to clause 1(a)(iii) shall have to stop manufacturing of such items within six months from the date of issue of this notification.

5. Any Violation of above provisions shall attract the penalty as follows: -

Violators	**Amount of Penalty**
Manufacturer	Rs 5.00 Lakh
Transporter	Rs 2.00 Lakh
Whole Sellers/ Traders	Rs 1.00 Lakh
Individual Users	Rs 100/-
For subsequent violation by the same legal entity shall attract twice the fine mentioned above.	

6. Following Officers are authorised for implementation of the directions and imposition of the penalty:-

i) District Magistrate or officer nominated by him not below the rank of Tehsildar.

ii) Municipal Commissioner/Executive Officer of the Urban Local Bodies or officer nominated by them not below the rank of sanitary supervisors.

iii) Superintendent of Police or officer nominated by him not below the rank of Inspector.

iv) Divisional Forest Officer or officer nominated by him not below the rank of Range officer.

v) Commissioner Tax Department or officer nominated by him not below the rank of joint commissioner.

vi) Commissioner Transport Department or officer nominated by him not below the rank of joint commissioner.

vii) Regional Officer, Pollution Control Board or officer nominated by him not below the rank of Asst. Engineer.

7. All the fines, so collected will be deposited with Finance department of Government of Uttarakhand under "Other Financial Receipt" Head.

(Anand Bardhan)
Principal Secretary

Letter No: (1) / XXXVIII-1-21-13(11)/2001, Dated as above.

Copy:

1. Secretary, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India.
2. Secretary, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India.
3. Chairman/Member Secretary, Cenetral Pollution Control Board, Government of India.
4. Chief Secretary, Government of Uttarakhand.
5. Secretary, Hon'ble Governor of Uttarakhand.
6. All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/Secretary (Incharge), Uttarakhand Secretariat.
7. Chief Resident Commissioner of Uttarakhand, New Delhi.
8. All Head of Department, Uttarakhand.
9. Commissioner, Kumaun/Garhwal, Uttarakhand.
10. All District Magistrate, Uttarakhand.
11. Director, State Environment, Conservation & Climate Change Directorated, Uttarakhand.
12. Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, Uttarakhand.
13. Commissioner, Tax Department/Transport Department, Uttarakhand.
14. Private Secretary of the Hon'ble Chief Minister, Government of Uttarakhand.
15. All Private Secretary of the Hon'ble Minister, Government of Uttarakhand.
16. Guard File.

16/7/21

(Neha Verma)
Additional Secretary

Annexure-4

Head Office

UTTARAKHAND ENVIRONMENT PROTECTION AND POLLUTION CONTROL BOARD
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun (Uttarakhand)

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

Phone: 0135-2658086, Fax: 0135-2718092 Web: www.ueppcb.uk.gov.in

पत्रांक सं0–यूईपीपीसीबी / एच.ओ / सा0–453 / 2019 / 2331–534, दिनांक :–25 06.2019

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून / टिहरी / पौड़ी / चमोली /
रूद्रप्रयाग / उत्तरकाशी / हरिद्वार / उधमसिंहनगर /
नैनीताल / चम्पावत / बाग़ेश्वर / अल्मोड़ा / पिथौरागढ।

विषय :– उत्तराखण्ड राज्य में प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट नियम, 2016 के कम में Producers, Importer and Brand Owners की जिम्मेदारी निर्धारण करते हुये उनके उत्पादों के माध्यम से जनित प्लास्टिक वेस्ट का एकत्रिंकरण एवं वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं, कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने हेतु प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट नियम, 2016 प्रख्यापित किया गया है।

उक्त नियम की धारा–2 (1) के अनुसार :–These rules shall apply to every waste generator, local body, Gram Panchayat, manufacturer, importers and producer. उक्त नियम की धारा–9 में Responsibility of Producers, Importer and Brand Owners के अन्तर्गत निम्न कार्यवाही किया जाना प्राविधानित किया गया है :

(1) The producers, within a period of six months from the date of publication of these rules, shall work out modalities for waste collection system based on Extended Producers Responsibility and involving State Urban Development Departments, either individualy or collectively, through their own distribution channel or through the local body concerned.

(2) Primary responsibility for collection of used multi-layered plastic sachet or pouches or packaging is of Producers, Importers and Brand Owners who introduce the products in the market. They need to establish a system for collecting back the plastic waste generated due to their products. This plan of collection to be sutmitted to the State Pollution Control Boards while applying for Consent to Establish or Operate or Renewal. The Brand Owners whose consent has been renewed before the notification of these rules shall submit such plan within one year from the date of notification of these rules and implement with two years thereafter.

(4) The producer, within a period of three months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette shall apply to the Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, of the States or the Union Territories administration concerned, for grant of registration.

(5) No producer shall on and after the expiry of a period of Six Months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette manufacture or use any plastic or multi-layered packaging from packaging of commodities without registration from the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committees.

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट नियम, 2016 के प्राविधानों के कियान्वयन की समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है, कि :–

1. वर्तमान में कोई भी Producers, Importer and Brand Owners द्वारा राज्य बोर्ड के समक्ष ऐसा Plan of Action प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनके उत्पाद द्वारा राज्य कुल कितना प्लास्टिक वेस्ट जनित किया जा रहा है एवं नियमानुसार कितना प्लास्टिक वेस्ट किन–किन माध्यमों से एकत्रिकरण कर वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण किया जा रहा है।
2. Producers, Importer and Brand Owners द्वारा न तो राज्य बोर्ड से रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया गया है, न ही रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिये नियमानुसार आवेदन किया गया है। बोर्ड से रजिस्ट्रेशन प्राप्त किये बिना राज्य में उत्पादों के माध्यम से प्लास्टिक वेस्ट जनित किया जाना एवं उनका एकत्रिकरण कर निस्तारण न किया जाना नियम विरूद्ध है।

प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट की धारा–12 में यह प्रावधान किया गया है, कि Prescribed authority – (1) The State Pollution Control Board and Pollution Control Committee in respect of a Union territory shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to registration, manufacture of plastic products and multi-layered packaging, processing and disposal of plastic wastes.

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में स्थित एवं कारोबार कर रहे समस्त Producers, Importer and Brand Owners से प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट नियम, 2016 की धारा–9 में प्राविधानित नियमों के आधार पर कार्यवाही नहीं करने के कारण नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

आपसे अनुरोध है, कि अपने–अपने जनपद में स्थित एवं कारोबार कर रहे समस्त Producers, Importer and Brand Owners से प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट नियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। नियमानुसार कार्यवाही नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सन्दर्भित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(आनन्द बर्द्धन) आई.ए.एस.
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

1. आयुक्त, गढवाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
2. सदस्य सचिव, यू0ई0पी0पी0सी0बी0, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि समस्त जिलाधिकारियों से समन्वय कर प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट नियम, 2016 का अनुपालन राज्य में कराया जाना सुनिश्चित् करें।

अध्यक्ष, 24/06/19
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

HEAD OFFICE
Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board
"Gaura Devi Prayavaran Bhawan"
46B, I.T. Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun

UEPPCB/HO/Gen. 76 (3) Vol-III/147 Date: 28.12.2019

To,

Director,
Urban Development Directorate,
31/62, Rajpur Road, Dehradun,
Uttrakhand.

Direction under Section 5 of Environment Protection Act, 1986.

WHEREAS, Central Government has made the Plastic Waste Management Rules, 2016 to implement these rules more effectively and to give thrust on plastic waste minimization, source segregation, recycling, involving waste pickers, recyclers and waste processors in collection of plastic waste fraction either from households or any other source of its generation or intermediate material recovery facility and adopt polluter's pay principle for the sustainability of the waste management system.

WHEREAS, Hon'ble NGT vides its order dated 20.07.2019 in matter of O.A. no. 247/2017 directed:-

1. UDDs ensure setting up of Collection, source segregation of disposal system for plastic waste.
2. SPCBs/PCCs, UDDs shall ensure to promote compostable carry bags certified by CPCB.
3. SPCBs/PCCs and UDDs to ensure prohibited litter of plastic waste at historical, religious, public places and dumping of Plastic waste on drains, river banks & sea beahes is prohibited.
4. SPCBs/PCCs and UDDs to prohibit ensure open burning of plastic waste.
5. SPCBs/PCCs and Municipalities should constitute squad to check illegal manufacturing, stocking, sale of <50 microns thickness plastic carry bags and uncertified compostable carry bags/ products in the market.

WHEREAS, Uttrakhand Environment Protection and Pollution Control Board written letter to UDD to compliances of above direction via letter no. UEPPCB/HO/5303/1064 dated 28.09.2018.

WHEREAS, No report submitted by UDD to UEPPCB in compliance to NGT order dated 2.07.2019 in matter of O.A. no. 247/2017.

WHEREAS, Hon'ble NGT vide its order dated 06.12.2019 in matter of O.A. 247/2019 directed:-

1. SPCBs/PCCs should direct to UDDs to ensure setting-up of collection, source segregation & disposal system for plastic waste.
2. SPCBs/PCCs shall provide the details such as quantification, characterization & disposal methods of plastic waste. The details of disposed plastic waste should be provided to CPCB.
3. SPCBs/PCCs, UDDs shall ensure to promote compostable carry bags certified by CPCB.

4. SPCBs/PCCs and Municipalities should constitute squad to check illegal manufacturi stocking sale of <50microns thickness plastic carry bags and uncertified compostabl carry bags/ products in the market.
5. SPCBs/PCCs and UDDs to ensure prohibit litter of plastic waste at historical, religious, public places and dumping of plastic waste on drains, river, banks & sea beaches is prohibited.
6. SPCBs/PCCs and UDDs to prohibit ensure open burning of plastic waste.
7. States/UTs should frame a time targeted action plan covering the action points related to plastic waste segregation, collection and recycling/reuse of plastic waste.
8. Number of ULBs which have set-up of plastic waste management system as per rule 6(ii) (Including collection, segregation, and channelization & processing of plastic waste).
9. Number of ULBs having facilities for Collection of Segregated waste.
10. Number of ULBs having Material Recovery facility.
11. Status of Utilization of plastic waste (Annual Report form VI pt.4).
12. Quantity of Plastic waste utilized in recycling (TPD).
13. Quantity of plastic waste utilized in recycling road construction.
14. Quantity of plastic waste used in other purpose (please specify).
15. The States/UTs may submit their compliance reports to CPCB quarterly in a cumulative format failing which compensation of Rs. 1 lakh per quarter shall be levied by the CPCB.

And now there; In view of the above observations and exercising powers conferred in **section 5 of Environment Protection Act, 1986** the following direction issued to Urban Development Directorate:

1. To provide Action Taken Report in compliance of Hon'ble NGT order dated 02.07.2019 and 06.12.2019 in the matter of O.A. no. 247/2019.
2. To ensure proper management of plastic waste in accordance with the provision of PWM Rules, 2018.
3. To submit Action Taken Report to the Board annually as mentioned in rule-17 of PWM Rules, 2016 by the 30th April.

Receipt of these direction shall be acknowledged immediately and action taken on the above direction to be communicated to UEPPCB with in 30 days of recipt of these direction.

This issued with the approval of competent authority.

(S.P. Subudhi)
Member Secretary

Copy to: - Secretary, Urban Development Department, Uttrakhand Government, Dehradun for kind information pleases.

Member Secretary

HEAD OFFICE
Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board
"Gaura Devi Prayavaran Bhawan"
46B, I.T. Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun

UEPPCB/HO/Gen-76-Vol-III/148 Date: 28.12.2019

To,

District Magistrate,
Dehradun, Haridwar, Pauri Gharwal, Uttarkashi,
Chamoli, Rudrapryag, Tehri Gharwal, Nainital,
Pithoragarh, Champawat, Bageshwar, Udham Singh Nagar,
Almora, State- Uttrakhand.

Sub: - Direction under Section 5 of Environment Protection Act, 1986.

Sir,

WHEREAS, Central Government has made the Plastic Waste Management Rules, 2016 to implement these rules more effectively and to give thrust on plastic waste minimization, source segregation, recycling, involving waste pickers, recyclers and waste processors in collection of plastic waste fraction either from households or any other source of its generation or intermediate material recovery facility and adopt polluter's pay principle for the sustainability of the waste management system.

WHEREAS, Hon'ble NGT vide its order dated 06.12.2019 in matter of O.A. 247/2019 directed:-

1. SPCBs/PCCs should also ensure that no unregistered plastic manufacturing/recycling units is in operation & no unit is running nonconforming/residential areas. Besieds, it is also to be ensured that plastic carry bags/films <50 microns thickness should not be manufactured, stocked, sold and used in cities/ towns.
2. SPCBs/PCCs and UDDs to ensure prohibit ensure open burning of plastic waste.
3. Number of unregistered plastic manufacturing/recycling unit in State.

And now there; In view of the above observations and exercising powers conferred in **section 5 of Environment Protection Act, 1986** the following direction issued:-

1. To identify and report to the Board about unregistered manufacturing/recycling unit in your jurisdiction to ensure that they do not operate without obtaining consent under Air and Water Act and registration under PWM rules, 2016 from UEPCCB.
2. To ensure that plastic bags/films < 50 Microns thickness should not be manufactured, stocked, sold and use in your jurisdiction.
3. To ensure proper management of plastic waste in accordance with the provision of PWM Rules, 2016.

Receipt of these direction shall be acknowledged immediately and action taken on the above direction to be communicated to UEPPCB with in 30 days of recipt of these direction.

This issued with the approval of competent authority.

(S.P. Subudhi)
Member Secretary

Copy to: - Secretary, Urban Development Department, Uttrakhand Government, Dehradun for kind information pleases.

Member Secretary

Annexure-4

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
Web : www.ueppcb.uk.gov.in. E-mail : msukpcb@yahoo.com

पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/ HB-518, /2021/ 1926-384, दिनांक :-20, 07.2021

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून/चमोली/हरिद्वार/रूद्रप्रयाग/बागेश्वर/
टिहरी/पौड़ी/नैनीताल/चम्पावत/
उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा/उत्तरकाशी/पिथौरागढ़।

विषय :- Single use Plastic Carry Bags & Cutlery Items पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0-84/XXXVII-1-20-13(II)/2001 दिनांक 16.02.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त अधिसूचना के बिन्दु सं0-1 के अनुसार।

1. (क) कोई भी व्यक्ति, स्वयं या किसी और के माध्यम से जानबूझकर या अनजाने में निम्नलिखित प्लास्टिक/थर्मोकोल/स्टायरोफोम सामान के कया, विक्रय, उत्पादन, आयात, भण्डारण, ले जाना, उपयोग व आपूर्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में नहीं करेगा :-

(एक) किसी भी आकार, मोटाई, माप व रंग के प्लास्टिक कैरी बैग (हैंडल के साथ अथवा बिना हैंडल के) और नान-वोवन पाली प्रोपाईलिन बैगः

परन्तु बायो-कम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग एवं 50 माईक्रोन से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग, जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन में उपयोग किये जाते हैं, पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(दो) थर्मोकोल (पालीस्टायरीन), पालीयुरेथेन, स्टायरोफोम और इसी तरह के बने एकल उपयोग के डिस्पोजेबल कटलरी या प्लास्टिक जैसे प्लेट, ट्रे, कटोरे, कप, गिलास, चम्मच, कांटा, स्ट्रॉ, चाकू आदि चाहे वे किसी भी आकार व प्रकार के हों।

(तीन) एकल उपयोग खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग कन्टेनर चाहें किसी भी आकार, माप, प्रकार व रंग के हों, जो पुनः चकित प्लास्टिक से बने हों व जो खाद्य/तरल पदार्थ को ढ़कने, ले जाने व भण्डारित करने में उपयोग होता हो।

नोट : कम्पोस्टेबल प्लास्टिक भारतीय मानक की पुष्टि करेगा। बायो कम्पोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माता या विक्रेता विपणन या विकया से पहले केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस हेतु सहमति प्रमण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अधिसूचना के बिन्दु सं0-(4) के अनुसार :-

4. ऐसी सभी उत्पादन इकाईयां जो बिन्दु सं0-1(क)(एक) से बिन्दु सं0-1(क)(तीन) में निर्दिष्ट उत्पाद बना रही हैं, उनको इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि के छः माह के भीतर उपरोक्त उत्पादों का उत्पादन बन्द करना होगा।

..क्रमशः पृष्ठ-2

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248001

पत्रांक–यूकेपीसीबी/एच.ओ./1972-5/3/1925-383, दिनांक 20.07.2021

सेवा में,

श्री आशुतोष शुक्ला,
उप सचिव,
पर्यावरण, सरंक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषयः– **Single Use Plastic (SUP) को मिशन मोड में समाप्त करने हेतु विशेष कार्य बल गठित करने एवं व्यापक कार्य योजना (Comprehensive Action Plan) बनाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 168/XXXVIII-1-21-13(11)/2001, दिनांक 17.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के ज्ञापन सं0 84/XXXVIII-120-13(II)/2021, दिनांक 16.02.2021 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में प्लास्टिक को प्रतिबन्ध किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना के उल्लंघन की दशा में जुर्माना एवं निर्देशों के क्रियान्वयन और जुर्माना आरोपित किये जाने हेतु आधिकारी अधिकृत किये गये हैं। (छायाप्रति संलग्न)

अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार विशेष कार्यबल (Special Task Force) प्रस्तावित किया जाता है:–

1. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष
2. निदेशक, पर्यावरण, सरंक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय – सदस्य सचिव
3. सचिव/निदेशक, शहरी विकास विभाग – सदस्य
4. सचिव/निदेशक, पंचायती राज विभाग – सदस्य
5. सचिव/आयुक्त, परिवहन विभाग – सदस्य
6. सचिव/आयुक्त, कर विभाग – सदस्य
7. सचिव/हैड ऑफ फॉरेस्ट, वन विभाग – सदस्य
8. सचिव/निदेशक, उद्योग विभाग – सदस्य

उपरोक्त विशेष बल के गठित होने के पश्चात् गठित समिति के सदस्यों की प्रथम बैठक में टर्म्स ऑफ रिफरेन्सस (Terms of Reference) बिन्दुओं पर चर्चा किया जाना उचित होगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(एस0पी0 सुबुद्धि)आई0एफ0एस0
सदस्य सचिव